FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

M/S BHA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	BHA Associates Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	12/08/1999
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / Registered	RoC-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No.of corporate debtor	U18101DL1999PTC101143
5.	Address of the registered office and principal office (if any) ofcorporate debtor	40/43, Second Floor, C. R. Park New Delhi-110019
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	27/10/2019
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	10/05/2021 (Copy of Order received on 11th May 2021 based on information in website of NCLT)
8.	Name and registration number of the insolvency professionalacting as liquidator	Name – Pawan Kumar Agrawal Registration No. - IBBI/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with theBoard	Address – Pawan Kumar Agrawal L-2/37A, Ground Floor, Ekta Square, DDA, Kalka Ji, New Delhi - 110019 Email – irp@ppglegal.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with theliquidator	Address – Pawan Kumar Agrawal 40/55, First Floor, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019 Email – irp@ppglegal.com
11.	Last date for submission of claims	10/06/2021

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the BHA Associates Private Limited on 10th May 2021 under section 33 of the Code.

The stakeholders of BHA Associates Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10th June 2021, to the liquidator at the address mentioned against item No.10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. The prescribed forms may be downloaded from following link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

IBBI/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435 PAWAN KUMAR AGRAWAL B.COM. FCA

Mr.Pawan Kumar Agrawal
Liquidator
In the matter of BHA Associates Private Limited
IBBI/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435

Date: 14th May 2021
Place:- New Delhi

महाराष्ट्र में लगी पाबंदियां एक जून तक बढ़ाई गईं

मुंबई, 13 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की शृंखला तोड़ने के लिए लगाई पूर्णबंदी जैसी पाबंदियां गुरुवार को एक जून तक बढ़ा दी। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेंगी।

आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली 'आरटी-पीसीआर' रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।

आदेश के अनुसार, 'संवेदनशील क्षेत्रों' (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर भी लागू होंगी।

उसके अनुसार, माल वाहनों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

राज्य में पाबंदियां पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।

नए आदेश के अनुसार, स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ग्रामीण बाजारों और एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समितियों) की विशेष निगरानी करेंगे, ताकि कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने कहा कि अगर पाया गया कि इन स्थानों पर अनुशासन सुनिश्चित करने में परेशानी आ रही है, तो स्थानीय डीएमए इन्हें बंद करने का आदेश दे सकता है या कुछ अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकता है।

उन्नाव में गंगा घाट पर शवों के बरामद होने की जांच का आदेश

उन्नाव (उप्र) 13 मई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की बीघापुर पाटन तहसील में गंगा नदी के बक्सर घाट पर दफनाए गए कई शव बरामद होने पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इन दफनाए गए शवों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया।

उन्नाव के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उप जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जांच के लिए मौके पर भेजा गया है और वह शीघ्र ही पूरे मामले की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बताया कि बक्सर घाट कई जिलों की सीमा पर स्थित है और यह रायबरेली, फतेहपुर उन्नाव को जोड़ता है, वहां पर कई जिलों के लोग आकर परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं।

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) बीघापुर दया शंकर पाठक ने बताया, 'जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ मौके पर जाकर मैने निरीक्षण किया है, कहीं कोई शव खुले में पड़ा नहीं दिखाई दिया। दफनाए गए शवों की संख्या को लेकर भी उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।'

अधिकारी ने बताया, 'मुझे सूचना मिली है कुछ लोगों द्वारा रेत के नीचे शवों को दबाया गया है। सूचना मिलने के बाद तत्काल उप जिलाधिकारी को भेजा गया है। जो भी स्थिति है उसको देखते हुए सम्मानजनक जो भी कार्यवाही है वो करवाएंगे, इस तरह की स्थिति दोबारा न हो इसके लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।'

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) बीघापुर दया शंकर पाठक ने बताया, 'जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ मौके पर जाकर मैने निरीक्षण किया है, कहीं कोई शव खुले में पड़ा नहीं दिखाई दिया। दफनाए गए शवों की संख्या को लेकर भी उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।' इस घाट के पास रहने वाले ग्रामीणों का कहना था कि बृहस्पतिवार सुबह से ही किसी को भी शव दफनाने नहीं दिया जा रहा है, सभी को दाह संस्कार के लिए कहा जा रहा है।

कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रकों की जब्ती के मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कालरा के खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप हैं और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया जाना जरूरी है। गिरफ्तारी की आशंका के चलते कालरा ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। कालरा ने दावा किया कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच से जुड़ना चाहता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने कालरा की याचिका खारिज कर दी और कहा, 'आरोपी और कई सारे सह-आरोपियों के बीच रची गई पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया जाना जरूरी है।' हाल में की गई छापेमारी के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां 'खान चाचा', 'नेगा जू' और 'टाउन हॉल' से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और ऐसा संदेह है कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया है।

ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 के इलाज में महत्त्वपूर्ण चिकित्सकीय उपकरण हैं। अदालत ने कहा, 'आरोपी अब तक जांच से नहीं जुड़ा है। आरोपी के मोबाइल फोन में ग्राहकों के साथ वाट्सएप चैट, सह-आरोपियों के साथ बातचीत के कॉल के विवरण होंगे और उसके अकाउंट पर रोक लगाने की जरूरत है।' न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने और अभियोजन के गवाहों को भी डराने-धमकाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने कहा, 'इसलिए उसकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने का सवाल ही नहीं उठता।'

घर में कलाबाजी करते वक्त लड़के की मौत

सूरत, 13 मई (भाषा)।

गुजरात के सूरत शहर में 13 साल के लड़के की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई, जब वह अपने घर में कथित तौर पर स्टंट कर रहा था और रस्सी उसकी गर्दन के आसपास फंस गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लड़के के माता-पिता के अनुसार आठवीं कक्षा का छात्र स्टंट की वीडियो बनाता था और उन्हें सोशल मीडिया व वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर डालता था। सरथाना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर एमके गुर्जर ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम की है।

भरूच अस्पताल के न्यासियों के खिलाफ प्राथमिकी

भरूच, 13 मई (भाषा)।

पुलिस ने भरूच स्थित कोविड-19 अस्पताल के कुछ न्यासियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जहां इस महीने की शुरुआत में आग हादसे में 16 मरीजों समेत 18 लोगों की जान चली गई थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी भरूच के 'बी' संभाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (ए) के तहत बुधवार को मामला दर्ज की गई। पुलिस निरीक्षक बीएम परमार ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) विकास सुंदा सरकार की तरफ से इस मामले में शिकायतकर्ता हैं।

एक मई को 'वेल्फेयर अस्पताल' के आइसीयू वार्ड में आग लगने से कोविड-19 के 16 मरीजों और दो प्रशिक्षु नर्सों की मौत हो गई थी। यह अस्पताल एक परोपकारी ट्रस्ट चलाता है। परमार ने बताया कि बंबई पटेल वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष खालिद पटेल और ट्रस्ट के अन्य न्यासियों एवं मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के मुताबिक, घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बॉम्बे पटेल वेल्फेयर सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल की दो इमारतें हैं – एक पुराना परिसर और एक नया भवन।जिलाधिकारी ने निर्दिष्ट कोविड–19 अस्पताल चलाने की इजाजत पुरानी इमारत में दी थी लेकिन अधिकारियों को सूचित किए बिना प्रबंधन ने कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल नई इमारत में शुरू किया।

Monsoon to hit Kerala coast on May 30, says Skymet

FE BUREAU
New Delhi, May 13

PRIVATE WEATHER FORECASTER Skymet on Thursday predicted that southwest monsoon would hit the Kerala coast on May 30, two days before the usual onset date, because of a possible storm in the Arabian sea.

"The onset of southwest monsoon over Kerala is likely to be on May 30, with a model error of +/- 2 days," Skymet said in a statement. India Meteorological Department (IMD) will release its onset forecast on Saturday.

Last year, IMD had initially predicted onset on June 5, with a model error of +/- 4 days and later revised it to June 1, which proved correct, after a cyclonic circulation over the Bay of Bengal helped in the progress of monsoon. Usually, monsoon arrives on Kerala coast in June and spreads to most of rest of India by mid-July.

Monsoon onset* over Kerala

	IMD Forecast	Actual Onset
2016	June 7	June 8
2017	May 30	May 30
2018	May 29	May 29
2019	June 6	June 8
2020	June 5	June 1

*Normal is June 1

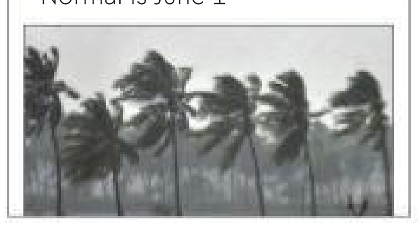

After two successive years of 'above-normal' rainfall, the country would witness 'normal' south-west monsoon this year with precipitation at 98% of the long period average (LPA) of 88cm, IMD said last month releasing its first forecast, which is scheduled to be updated by end of this month.

If the prediction holds true, it would augur well for food grains production, and thereby the agriculture gross value added (GVA), but such forecasts have not always been accurate. Skymet, on the other hand, sees the monsoon precipitation at 103%, with an error margin of +/- 5%.

"Onset of south-west monsoon over Kerala is largely influenced by the oceanic conditions, both in the Arabian Sea and Bay of Bengal. A likely cyclone formation in the Arabian Sea will be consequential for advance of monsoon stream over Indian waters. "However, tropical storm 'Tauktae' will vacate the Indian region by May 22, following which the westerly winds and cross equatorial flow will strengthen over the Arabian Sea. This also will be assisted by the MJO (Madden Julian Oscillation) entering Indian Ocean with moderate amplitude. Pre-monsoon showers will be intense and hefty over Kerala," Skymet said.

Though grains output has risen in recent years and agriculture sector in FY20 and FY21 remained a bright spot in the sagging economy, the link between overall monsoon rains and agricultural production has been rather tenuous. Of course, distribution and duration of rains do have a role in production of key grains, given that 52% of the crop area is still rain-fed. The monsoon rains are crucial for kharif crops like paddy, pulses and oilseeds and help boost soil moisture for the rabi crop.

"The seasonal rainfall this year is likely to be normal across the country, barring Odisha, Jharkhand, Bihar, Assam and eastern Uttar Pradesh," M Rajeevan, secretary at ministry of earth sciences, had said. Many parts of the eastern region may experience below normal rainfall.

Rainfall ranging between 96-104% of LPA is considered 'normal' while anything between 90-96% of LPA is 'below normal'. Similarly, precipitation between 104-110% of LPA is 'above normal' and below 90% is 'deficient'.

Likely GI tag in EU seen to boost India's basmati rice exports

PRABHUDATTA MISHRA
New Delhi, May 13

AN IMMINENT AGREEMENT on the geographical indications (GI) with European Union (EU) could boost India's basmati rice exports to \$500 million in 1-2 years from the current \$250 million as realisation is expected to increase with the quality-conscious consumers, officials say.

The independent observers said the shipments might not see any significant increase in volume in the short term unless there are concerted efforts to find buyers in countries, other than the United Kingdom (UK). However, price realisation will see an improvement with GI as the authenticity of pure basmati will be maintained.

India had exported \$ 245.4 million worth of basmati rice to EU countries (including the UK) during April-January of FY21, up from \$ 207 million during the entire 2019-20. The share of the UK in terms of volume has been nearly half in the total shipments of basmati sent to the EU region and the country also among the top 10 destinations of export of the aromatic Indian rice.

The price realisation in the UK has been lower, compared to many other countries. For instance, during April-January of 2020-21, Indian basmati exporters earned \$16 million more despite shipping 4,000 tonne less rice to Kuwait compared to the UK. The export to the UK was about 1,48,500 tonne during the 10 months of FY21.

"The current pending registration of basmati GI in EU and proposed India and EU GI agreement could be pursued to our advantage. Beyond basmati, there is an immediate opportunity in textiles and handicraft GI," said S Chandrasekaran, a trade policy analyst and author of a book on basmati GI. However, when compared to the GI products of both countries, the consumption of EU's produce in India can be immediate whereas Indian products are required to be nurtured, he said.

India and the EU last week agreed to enhance the bilateral trade and investment relationship through the resumption of negotiations for a balanced, ambitious, comprehensive and mutually beneficial trade agreement, eight years after its suspension. The two sides also agreed to launch negotiations for two key pacts on investment protection and GI.

"India has more agriculture, food, handicraft, artisan products under GI while in case of EU, more than 72% of its GI product sales come from wine and spirits. The principles and objectives of the proposed GI agreement will differ sharply due to 'definition of culture' and product segments," Chandrasekaran said. For instance, the EU applied for registration of 121 products in India out of which 92 belong to the wine and spirit category, he said adding EU will increasingly look for facilitation in GI product registration and market access.

Despite the pandemic and overall exports slump, India posted impressive growth in exports of agriculture and allied products in FY21, with buoyant shipments of a host of commodities including non-basmati rice, wheat, soya meal, spices, sugar, cotton, fresh vegetables, processed vegetables and alcoholic beverages. As per the data for the April-February period of last fiscal, India's foreign trade balance in agriculture increased by 41% on year to ₹1,32,580 crore.

Agriculture and allied products of ₹2.74 lakh crore were exported in the first 11 months of the last fiscal as against ₹2.31 lakh crore in the year-ago period, up 18.6%, while imports marginally increased by 3% to ₹1.41 lakh crore. India has consistently maintained a trade surplus in agricultural products over the years. The country's agricultural and allied sectors' exports were ₹2.52 lakh crore and imports were ₹1.47 lakh crore during FY20.

ONGC removes marketing margin but refuses to lower gas price

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 13

STATE-OWNED OIL and Natural Gas Corporation (ONGC) has agreed to do away with charging users a marketing margin on the gas it plans to produce from its KG basin field but refused to lower the minimum rate, according to tender documents.

ONGC, India's top oil and gas producer, last month sought bids for sale of initial 2 million standard cubic meters per day of gas from its KG-DWN-98/2 block (KG-D5).

The company asked bidders to quote a rate linked to prevailing Brent crude oil prices. It fixed the floor or minimum rate at 10.5% of the three-month average Brent crude oil price. On top of it, the firm sought \$0.20 per million British thermal unit.

Potential bidders however opposed the levy of the marketing margin as well as the "high" floor price.

Responding to queries raised by bidders, ONGC said the floor price cannot be changed but marketing margin is being dropped.

UP discoms' dues to state-run gencos reach staggering ₹17,000 cr

DEEPA JAINANI
Lucknow, May 13

THE UTTAR PRADESH electricity distribution companies (discoms) dues to the state-run generation utilities, such as Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam (UPRVUNL), UP Power Transmission Corporation (UPTCL) and UP Jal Vidyut Nigam have soared to ₹17,000 crore.

Though the Centre's liquidity infusion scheme under the Atmanirbhar Bharat package helped these discoms to bring down dues to central public sector units (CPSUs) and independent power producers (IPPS) down from ₹27,000 crore to ₹5,688 crore at the end of March 2021, the dues remain staggeringly high.

Speaking to *FE*, M Devaraj, chairman of UPPCL as well as the three-state utilities, said that while the discoms owed UPRVUNL ₹10,500 crore, the dues of UPTCL stand at ₹5,800 crore and that of UPJVN's at ₹650 crore. It may be mentioned that UPRVUNL is a wholly-owned state thermal power company, having a generating capacity of 5474 MW. It operates four thermal power stations within the state, Anpara, Obra, Harduaganj and Parichha.

"Depending on fund availability, we try to give money to the state gencos, too, to meet their requirements, but ultimately everything boils down to revenue. The more revenue we get from the consumers, the more we can pass it on to the different generators," Devaraj said.

UPPCL's total expenses, including O&M, is around ₹77,000 crore per annum, against which it gets a government subsidy of around ₹12,000 crore. The power purchase cost comes to around ₹60,000 crore per annum, against this, the revenue mopped up is approximate ₹40,000 crore per annum.

"There is usually a gap of ₹1,200 crore to ₹1,500 crore per month between the power purchase cost and the revenue realized from the consumers. With the current revenue, it's challenging to even meet the salaries of the employees. So, mopping up revenue is our biggest challenge. For that, we are also trying to track unmetered consumers and those consumers who have never paid bills. But, in the present Covid scenario, we cannot do much. Our main focus right now is to maintain supply. Once things improve, we will start focusing on other things," said Devraj, adding that while the peak demand for power is roughly around 20,000 MW, the mix of consumers has changed due to Covid-19.

"Most commercial establishments are closed now, and there is more demand from the domestic side, which is a subsidised sector. Hence, meeting the revenue targets has become all the more difficult," he added.

Speaking to *FE* on the condition of anonymity, an official of the UPRVUN said that the UPPCL releases as much money to the entity as is necessary to meet its basic needs. "Only that much amount is released as is required to run a powerhouse, including money for coal, establishment cost, funds for O&M and bank loan repayments for the new projects that are in the works, such as Anpara D, Parichcha, Harduaganj extension, etc," he said, adding that while a lot of pressure is exerted to clear the dues of the CPSUs and IPPS, no one seems to be bothered about clearing the dues of state gencos, mainly because it is an in-house entity.

Interestingly, while all the generating companies get 14% RoE, UPRVUNL's RoE is only 2%. "Since the equity belongs to the government, the board of directors of UPRVUN decided a couple of years back that it will take only 2% RoE," the source said, requesting anonymity.

Court issues show-cause notice to Nirav Modi in PNB scam case

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, May 13

A SPECIAL COURT here has issued a public notice to fugitive diamond merchant Nirav Modi, wanted in India for alleged fraud and money laundering in the PNB scam case, asking why his properties should not be confiscated under the Fugitive Economic Offenders (FEO) Act.

Special Judge V C Barde has also asked Modi to appear before the court on June 11.

The court said if the accused failed to appear, it will proceed with action against him under the FEO Act. The special court had in December 2019 declared Nirav Modi a fugitive economic offender, on a plea of the Enforcement Directorate (ED), which is conducting a probe into the case.

"I, V C Barde, Special Judge, PMLA, 2002 and Fugitive Economic Offenders Act, 2018, issue NOTICE to you to show cause as to why the properties mentioned in the application (ED's plea), in which you have pecuniary interest and/or otherwise, should not be confiscated under the said Act," the recent notice said.

A similar notice was also issued to Nirav Modi's wife Ami, sister Purvi and brother-in-law Maiank Mehta.